

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No 9944/2023 Ms. Rahat Zubair C/o Mohammad Zubair, R/o 228, Mission Chowk, Ishwaripura, Ward Number 24, Murwara, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Bhaganwara Dolomite Mine in an area of 2.10 ha. Dolomite Mine – 26,966 Tonne per annum, Lateritic Soil – 2299 cum per annum and Mine Waste – 2544 cum per annum) (Khasra No. 109), Village- Bhaganwara, Tehsil- Badwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 109), Village- Bhaganwara, Tehsil- Badwara, District-Katni (MP) 2.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक राहत जुबेर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1813 दिनांक 03/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

प्रस्तावित खदान निजी भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा में 400 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर से उत्तर-पश्चिम दिशा में एक कच्चा रोड़ प्रतीत हो रहा है । इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है ।

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एक पगडंडी रास्ता खदान के समीप से निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस पगडंडी का उपयोग ग्रामीणों द्वारा नहीं किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाईट – 26,966 मी³ प्रति वर्ष, Lateritic Soil – 2299 मी³ प्रति वर्ष एवं माईन वेस्ट – 2544 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.34 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 09.18 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 04.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

Commitment For CER Activities		
SN	Issues	Cost in RS
1	One warmer machine, one AC (2tonne), 4 complete bed at primary Health center Devri Hatai	2.50
2	Contribution of fund to EDC committee of Bandhavgarh National Park	2.00
Total		4.50
Commitment For CSR Activities		
SN	Issues	Cost in RS
1	Provision of medical Ambulance for near by villagers with driver and maintenance facility on free of cost throughout the mine life	2% of project cost (Rs 1.0 Lac per year i.e. total 30 lacs for ML period)

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
Within lease area			
1 st and 2 nd Year	In barrier zone (673m *7.5m = 5047sqm) and other area	Three Row of Neem in the periphery and barrier zone . Fruit bearing trees at other non minable area and over dump area	2000

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

Total			2000
1 st to 2 nd year	Transport route (536m)	Karanj, Mango, Neem, Jangle Jalebi, Imli etc and other local species	430
1 st year	Village distribution	Mango, Neem, Anwla, Jam, Munga etc and other local species	1000
Grand total			3430

2. Case No 8705/2021 M/s. Mahalaxmi Mines Mineral, Ward No. 4, Kymore Tehsil - Katni, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.88 ha. (109414 cum per annum) (Khasra No. 210/1 क, 210/1ख, 210/1 ग, 210/2क, 210/2ख, 210/2ग, 210/3 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 211/1 क, 211/2, 212, 215/2, 215/3, 216), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 210/1 क, 210/1ख, 210/1 ग, 210/2क, 210/2ख, 210/2ग, 210/3 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 211/1 क, 211/2, 212, 215/2, 215/3, 216), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 4.88 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 522वीं दिनांक 27/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

3. Case No 9945/2023 M/s. Govind Coal Private Limited, Director, Shri Mukesh Khurana, R/o 217/1, Dubey Colony, Rafi Ahmad Kidwai Ward 15, Tehsil & District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Gubradhari Dolomite Mine in an area of 4.84 ha. (49995 Tonne per annum) (Khasra No. 521), Village-Gubradhari, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 521), Village-Gubradhari, Tehsil-Murwara,

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

District-Katni (MP) 4.84 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश खुराना ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 2325 दिनांक 17/10/2022 द्वारा उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा / खनिपट्टे के 500 मीटर के परिधि में 01 अन्य खनि रियायत मेसर्स ठाकुर रामनिवास सिंह मिनरल्स प्रा.लि. के पक्ष में ग्राम टेढ़ी, तहसील मुड़वारा के खसरा नंबर 284 भाग रकबा 4.90 हे. क्षेत्र पर खनिज मार्बल का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होना पाया जाता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित खनिज डोलोमाईट एवं 500 मीटर की स्वीकृत अन्य खदान मार्बल (04.90 हे.) एक-दूसरे की सदृश खदानें नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में एक कच्चा रोड़ निकलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में जा रहा है इस संबंध में 10 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है जो सरफेस मेप में दर्शाया गया है। लीज क्षेत्र में 07 पेड़ दिख रहे हैं, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 03 पेड़ काटे जायेंगे एवं उसके एवज में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। समिति की परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि जो 03 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है उनके चारों ओर चार मीटर रेडियस छोड़ते हुए खनन कार्य नहीं करेंगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-69 के सरल क्रमांक-41 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लाईम डोलोमाईट- 49,995 टन प्रतिवर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 27.16 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 07.02 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु.
ग्राम गुबराधरी के शासकीय प्राथमिक शाला में 9 कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, कुर्सी के साथ और 9 अलमारी लाइब्रेरी के लिए	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	इमली, कटहल, आम, अमरुद बेल, आंवला, काला सिरस, सफेद सिरस, जंगल जलेबी, जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातिया	2000
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	210
3.	गुबराधरी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद ।	3760
4.	शासकीय विद्यालय गुबराधरी में	कचनार पुत्ररंजीवा मौलश्री और अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि ।	30
योग			6000

4. प्रकरण क्रमांक 9012/2022 - श्री मनु मल्होत्रा, वार्ड न. 1, बरही तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 209/2 रकबा 01.35 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-20,001 मी.³, ग्राम करोदीकलां तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 209/2 रकबा 1.35 हेक्टेयर, ग्राम ग्राम करोदीकलां तहसील बरही जिला कटनी जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

5. Case No 9957/2023 Shri Piyush Chandel, Owner, R/o Bishthan Road, District-Khargone (MP)-464001, Prior Environment Clearance for Mominpura Crusher Stone Deposit in an area of 1.00 ha. (Stone – 5000 Cum per annum and M-Sand – 3550 Cum per annum) (Khasra No. 05, 07), Village- Mominpura, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP)

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05, 07), Village- Mominpura, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष चंदेल ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 45 दिनांक 11/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 02.315 हे. है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 411 मीटर पर 02 शेड है, पूर्व-पश्चिम की ओर एक रोड़ निकल रहा है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड़ एवं परिवाहन मार्ग है, खदान क्षेत्र 02 भागो में है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि न्यूनतम 1.0 हे. तक का नियम होने के कारण लीज 02 भागो में स्वीकृत की गई।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन ने पत्र क्रमांक 229 दिनांक 04/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त पत्थर गिट्टी केशर उत्पनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,000 मी³ प्रति वर्ष प्रति एम-सेड – 3550 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.32 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.05 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक शाला मोमीनपुरा में 20 कुर्सिया और मेज़ की व्यवस्था प्रधान अध्यापक के लिए 1 कुर्सी और मजे	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, अगेव एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	75
3.	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	75
4.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
5.	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
योग			1000

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

6. Case No 9955/2023 M/s Sanwariya Seth Granites, Partner, Shri Himmat Singh, , R/o Ratanpur Road, Borawar, Tehsil-Makrana, District-Nagaur (RJ)-341502, Prior Environment Clearance for Narwa Granite Mine in an area of 1.80 ha. (1000 Cum per annum) (Khasra No. 1787), Village-Narwa, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP)

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1787), Village-Narwa, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP) 1.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री तारा अजनार ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 529 दिनांक 11/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 1.60 हे. है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान निजी भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर पहाड़ी क्षेत्र पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार दक्षिण दिशा में 264 मीटर पर नदी है, पश्चिम दिशा में 394 मीटर पर आबादी है एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 24 मीटर पर एक शेड है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो सेड बना हुआ है वह मशीन आदि रखने के लिये उपयोग में आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत नहीं की गई अतः बैरियर जोन में ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत करे।

7. Case No 9956/2023 Shri Govind Jadon, Owner, R/o Ananpur Road, Lateri, District-Vidisha (MP)-464114, Prior Environment Clearance for Okhlikheda Crusher Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 459/1, 458/2/4), Village-Okhalikhera, Tehsil-Lateri, District-Vidisha (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 459/1, 458/2/4), Village-Okhalikhera, Tehsil-Lateri, District-Vidisha (MP) 3.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोबिंद जादौन ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 851 दिनांक 25/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान निजी भूमि पर आवंटित है परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार दक्षिण दिशा में 143 मीटर पर एवं दक्षिण-पूर्व दिशा में 225 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्व दिशा में 443 मीटर पर मोबाईल टॉवर, 378 मीटर पर आबादी एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 300 मीटर पर प्राकृतिक नाला स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक 851 दिनांक 25/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।

प्रस्तुतकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान की सैधांतिक स्वीकृति दिखाई गई जो पी.पी. के रिस्तेदार के नाम थी जिसमें मशीनो के लिये सहमति दी गई है न कि खनन् कार्य के लिये अतः प्रस्तुत सहमति खनन् के अनुरूप नहीं है अतः परियोजना प्रस्तावक यथोचित सहमति पत्र प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी परीक्षण के दौरान आया कि भूमि की स्वाईल प्रोफाईल में 02 मीटर गहरी मिट्टी दिख रही है जिससे यह स्पष्ट है कि यह भूमि कृषि के लिये उपयोगी है न कि खनन् कार्य के लिये अतः खनिज अधिकारी विषय विशेषज्ञ से परीक्षण कराकर अपना अभिमत दे।

8. Case No 9413/2022 Smt. Sonal Rai, R/o Hotal Utsav Vilas, In Front of New Overbridge, Sagar-Damoh road, Hirdepur, Dist. Damoh (MP)-470661, Prior Environment Clearance for Laterite & Clay Quarry in an area of 10.150 ha. (1,40,562 TPA and 21,627 TPA) (Khasra No. 69), Village - Majhgawan, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP)

This is case of Laterite & Clay Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 69), Village - Majhgawan, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 10.150 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 609वीं दिनांक 07/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनल राय (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में शासकीय भूमि पहाड़ है, प्रश्नाधीन खदान में 09 पेड़ लगे हुए हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया जिनमें से 03 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। खदान के पूर्व दिशा में एक तालाब स्थित है जिसके लिये परियोजना प्रस्तावक ने 100 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है। वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 5254 दिनांक 16/09/21 अनुसार आवेदित/स्वीकृत क्षेत्र आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 110 से लगभग 142 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकरण की संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त है। खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है। बंजारी टोल एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जनसुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, मुक्तिधाम में सुधार व्यवस्था, गांव में पानी की व्यवस्था, रोजगार एवं वृक्षारोपण, भारी वाहन बस्ती ने निकले अन्य पहुचमार्ग की व्यवस्था संबंधी सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुए थे, जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्ताव ने बताया कि सभी सुझावों को ई. एम.पी./सी.ई.आर. में बजट सहित शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटराईट – 1,40,562 टन प्रतिवर्ष एवं क्ले – 21,627 टन प्रतिवर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 31.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.12 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु.
गांव में स्थित मुक्तिधाम में बैठने के लिए बेंच (रुपए 30,000/-) ग्राम पंचायत के माध्यम से लगवाई जाएगी तथा मुक्तिधाम के चारों तरफ फेंसिंग (रुपए 50,000/-) के साथ साथ चारों तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा एवं मुक्तिधाम में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप साथ ही साथ कांक्रिटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाने हेतु रुपए (रुपए 1,00,000/-) योगदान दिया जावेगा	1,80,000
बंजारी टोला गाँव के विकास कार्य हेतु आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में मरम्मत एवं पुताई करवाई जावेगी।।	50,000
ग्रामवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्राम बंजारी टोला में बालक शिक्षा संघ के लिए योगदान दिया जावेगा।	20,000
ग्राम बंजारी टोला में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप साथ ही साथ कांक्रिटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाने हेतु योगदान	50,000

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

दिया जावेगा।	
ग्राम मंझगवां तथा ग्राम बंजारी टोला में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए खाना बनाने के लिए बर्तन और जरूरत की वस्तुएं देने का प्रावधान है।	20,000
ग्राम मंझगवां तथा बंजारी टोला ग्राम के लोगों के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से रोगी कल्याण समिति में योगदान दिया जावेगा।	20,000
ग्राम बंजारी टोला में पशु स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से टीकाकरण के लिए योगदान दिया जावेगा।	10,000
कुल	3,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 12,300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन प्रथम वर्ष	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, कुल्लू, महुआ करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1600
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- पीपल, सेमल, बरगद, जंगल जलेबी, पुतरंजीवा, कुसुम इत्यादि।	280
3.	उत्तर पश्चिम दिशा में आवेदित क्षेत्र के समान्तर वृक्षारोपण (300 मीटर) पौधों की ऊँचाई : 2.5 फीट से 3 फीट	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, कुल्लू, महुआ करंज, बेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
4.	गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत (2.5 ha) पौधों की ऊँचाई : 2.5 फीट से 3 फीट	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:-, जंगल जलेबी, नीम, पीपल,, सीताफल, कुल्लू, महुआ करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
5.	ग्राम में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री, पाखड़ अन्य स्थानीय प्रजातिया। पूर्ण सुरक्षा के साथ	70
6.	ग्राम में स्थित मुक्तिधाम के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:-सिस्सू, कदम, बरगद, पाखड़, कचनार, पीपल, नीम आदि।	80
7.	ग्राम में स्थित आंगनवाड़ी के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:-सिस्सू, कदम, बरगद, चिरोल पाखड़, कचनार, पीपल, नीम आदि। पूर्ण सुरक्षा के	20

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

		साथ	
8.	उत्तर पच्छिम दिशा में आवेदित क्षेत्र के समान्तर वृक्षारोपण (300 मीटर) पौधों की ऊंचाई : 2.5 फीट से 3 फीट	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, कुल्लू, महुआ करंज, बेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
9.	आसपास के ग्रामीणों को वितरण के लिए ग्रामवासियों एवं पंचायत से परामर्श लेकर कुल 8900 पौधे वितरण किये जायेंगे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए अचार आदि स्थानीय पौधों की प्रजातियां	8900
योग			12,300

9. Case No 9949/2023 Shri Dileep Singh S/o Ashok Singh, Lease Owner, R/o Asha Niwas, Arjun Nagar, Pateri, Near Blooms Academy School, Raghuraj Nagar, District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Bathiya Stone Mine in an area of 2.50 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 376/3, 376/4, 376/5), Village-Bathiya, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 376/3, 376/4, 376/5), Village-Bathiya, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2298 दिनांक 03/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 41 मीटर पर एवं पूर्व दिशा में 240 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 269 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर-पूर्व 436 मीटर पर आबादी एवं उत्तर दिशा में 361 मीटर पर 01 से 02 मकान स्थित है। खदान के दक्षिण दिशा में 41 मीटर पर पक्का रोड़ है, जिसकी संरक्षण हेतु परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ कार्ययोजना प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना ने पत्र क्रमांक 874 दिनांक 08/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के दक्षिण दिशा में 41 मीटर पर एवं पूर्व दिशा में 240 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 269 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर-पूर्व 436 मीटर पर आबादी एवं उत्तर दिशा में 361 मीटर पर 01 से 02 मकान स्थित है ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर x 01 मीटर x 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

10. Case No 9946/2023 Executive Engineer, Water Resources Division, Nowgaon, Chhatarpur (MP)-471201, Prior Environment Clearance for Kathan Major Irrigation project on Dhasan Basin [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of CCA 15000 ha. , Live capacity 57.83MCM and dead storage 9.81MCM near Village-Amkhera, Tehsil-Bada Malhera, District-Chhatarpur (MP)

This is a case of Prior Environment Clearance for Kathan Midium Irrigation Project Scheme at near Village-Amkhera, Tehsil-Bada Malhera, District-Chhatarpur (MP). Midium Irrigation Project proposes to construct a dam across Kathan River (forms the

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

part of Dhasan Sub Basin) to store water during monsoon and to serve a command area of 15000 ha (CCA) . The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The case was presented by t PP Shri Nishesh Goswami, Executive Engineer, Water Resources Division, Nawgaon, Chhatarpur. The project has a CCA area of 15000 ha.

PP submitted following salient features of the project:

Sl. No.	PARTICULARS	DETAILS
1	S. No. In the schedule & project sector	1(c) River Valley / Irrigation projects – Irrigation project sector
2	Category of the project	Category – B1
3	Specific/general condition applicable	Specific / general conditions are not applicable
4	Proposed site/land details	Total Submergence area is 1293.39 ha. Out of which Submerged forest land is of 160.61 ha and Submerged non – forest land is of 1132.78 ha
5	Cultivable Command area / Annual Irrigation	15000 ha
6	Project cost	The total cost of the project is estimated at Rs.39271.18 Lakhs, 12 % GST & 3% Establishment charges has been included in the estimates.
7	Manpower details	25 people will be engaged
8	Details if project falls under the Purview of A) FCA,1980, B) WPA,1972, C) CRZ, 2011	The project falls under the purview of Forest Conservation Act, 1980. 160.61 ha of forest land falls under submergence Proposal for forest clearance has been applied in the Parivesh Portal bearing proposal number: FP/MP/IRRIG/424473/2023
9	CPA/SPA/ESA/ESZ, if any	It is not applicable as the study area doesn't falls under any of these criteria
10	Interlinked project, if any, with status	The project is not linked with any other project

PROJECT SPECIFICATIONS

Sl.	Particulars	Configuration	Sl.	Particulars	Configuration
-----	-------------	---------------	-----	-------------	---------------

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

No.			No.		
1	Type of Dam	Earthen dam	11	Head discharge required	5.25 cumecs
2	Dam height from the deepest foundation level (m)	12.87	12	Design flood discharge	6415.16 Cumecs
3	Length of the Dam (m)	(0 to 75 m & 240 to 405m)	13	Gross Command Area	19090 Ha
4	Type of spillways	Central Gated Spillway	14	Cultivable Command Area	15000 Ha
5	Number of spillway	2	15	Annual Irrigation Proposed	15000 Ha
6	Length of spillway	134	16	Kharif	0 Ha
7	Crest Level of weir	321.0 m	17	Rabi	15000 Ha
8	Number of gates		18	Length of rising main	2 km
9	Size of gates	12 m * 9 m	19	Length of gravity main	5 km
10	Benefit cost ratio	2.56	20	Total number of gravity mains	1
*	Number of villages affected	8	*	Number of villages benefitted	47

REHABILITATION AND RESETTLEMENT PLAN

- ❖ Only 4 villages namely Pipariya Kalan, Raipura Kalan, Dhanguan and Bineda will be subjected to submergence.
 - ❖ The population affected will be resettled and rehabilitated within 30 km radius of the project site.
 - ❖ Provision of basic amenities like medical, primary and secondary education, water supply, electricity, sanitation, etc will also be done for the people thereby.
 - ❖ The trees that will be cut down due to the project purpose will be compensated by planting 10 trees for 1 tree cut within 25 kms from the project site depending on the congenial conditions such as soil content, light exposure, micro climate etc.
- **Affected- 08** villages namely – Bineda, Manakpura, Pandajhir, Pipariya Kalan, Raipura Kalan, Sirbon, Dhanguan & Jhingiri are affected.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

- **Benefited (no.)** -47 villages benefited- Samretha, Bhagwan, Simariya(Bhagwan), Janakpur, Pathlakhera, Udannakhera, Madikhera, Kundalya, Madiya, Kabyiyan, Chapkan, Kudwari, Mathanikhera, Bann, Pura, Kusaal, Lidhora, Pathariya, Dharampura, Piprakalan, Footakhera, Satpaara, Kurra, Raniyakhera, Tamrankhera, Kamalkhera, Nayakhera, Barethi, Sendra(Maharajpur), Simariya, Gunanjnaya, Harpura, Manpaasar, Beeron, Tingri, Barguwan, Jagaapur, Khardouti, Gwalganj, Seror, Toro, Pathariya, Dharampura, Pathiya Pura Patti, Bhojpura, Kuwarpur, Sijwaha shall get benefited.
- There is 160.61 Ha. Forest land coming under submergence and 15.00 lakhs/Ha. cost is taken for compensation and catchment area treatment plan.

During presentation, PP submitted that the project falls under the purview of Forest Conservation Act, 1980.160.61 ha. of forest land falls under submergence Proposal for forest clearance has been applied in the Parivesh Portal bearing proposal number: FP/MP/IRRIG/424473/2023.

Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Since project involves 160.61 ha., forest area hence, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
2. Wild life conservation plan, Ecological services assessment.
3. Ecological damage assessment.
4. Soil conservation plan.
5. Catchment improvement plan through forest department (Revenue and Forest area)
6. Bifurcation of RF and PF details (if any).
7. Detailed diagrammatic representation of command area and any of the submergence area shall be prepared and appended with EIA report.
8. Status of land as per land record register of concerned collector.
9. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
10. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
11. Thematic diagram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
12. Details of actual area occupied by pipes and other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussed in the EIA report.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

13. Narmada Development Division has applied for distance from nearby National Park/ WLS vide letter no. 206 dated 13.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
14. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
15. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
16. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
17. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
18. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
19. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.
20. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

21. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
22. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
23. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
24. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
25. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
26. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
27. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
28. Muck management plan wrt machinery deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
29. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
30. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
31. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
32. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

11. Case No 9950/2023 Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sarwani Khurd Crusher Stone Deposit in an area of 3.00 ha. (14820 Cum per annum) (Khasra No. 173), Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 173), Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक विजयवर्गीय (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 502 दिनांक 02/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है, उत्तर दिशा में 359 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 59 मीटर पर नदी स्थित है। खदान के उत्तर भाग से कच्चा रोड़ एवं दक्षिण दिशा में 59 मीटर पर नदी स्थित है जिसकी संरक्षण योजना परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 502 दिनांक 02/03/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के उत्तर भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है, उत्तर दिशा में 359 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 59 मीटर पर नदी स्थित है। खदान के उत्तर भाग से कच्चा रोड़ एवं दक्षिण दिशा में 59 मीटर पर नदी स्थित है जिसकी संरक्षण योजना परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

12. Case No 9952/2023 Shri Vivek Dubey, Partner, M/s Stone Works Mining, R/o Ram Manohar Lohiya Ward, Nadipur, Infront of Pali Threshers, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Malhan Dolomite Mine in an area of 2.80 ha. (100385 Tonne per annum) (Khasra No. 297), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 297), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) 2.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विवके दुवे (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एंड एम साल्यूशन नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 221 दिनांक 08/02/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान निजी भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 264 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 317 मीटर पर कच्चा रोड़ है, इनके संरक्षण हेतु कार्ययोजना परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे । खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ दिख रहे हैं अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान क्षेत्र पुराना पिट है अतः इसके विवरण ईआई के साथ प्रस्तुत किया जावे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

1. खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 264 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 317 मीटर पर कच्चा रोड़ है, इनके संरक्षण हेतु कार्ययोजना परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान क्षेत्र पुराना पिट है अतः इसके विवरण ईआई के साथ प्रस्तुत किया जावे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

13. Case No 9954/2023 Shri Vishal Lele, Sr. RSM, M/s Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, KAPL House, Arka The Business Centre, Plot No.37, Site No.34/4, NTTF Main Road, Peenya Industrial Area, 2nd Phase, District-Bengaluru (KA)- 560058, Prior Environment Clearance for Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited in an area of 202343 Sqm. (Manufacturing Products 1000 MT/Year) at Plot No. 103& 104 and 110 to 116 at DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited in an area of 202343 Sqm. (Manufacturing Products 1000 MT/Year) at Vikram Udyogpuri, DMIC Village-Narwar, Tehsil-Ujjain, District- Ujjain (MP).

The case was presented by Env. Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve Indore, and PP Shri Vishal Lele, Sr. RSM, M/s Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited , wherein PP submitted following salient features of the project:

- Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (KAPL), is a Government of India Enterprise. It is a Joint Sector Company of Government of India with 59.17% of the

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

shareholding and 40.83% from the Government of Karnataka through Karnataka State Industrial Infrastructure Development Corporation (KSIIDC). From a modest beginning in 1984, KAPL has grown exponentially in the areas of manufacturing and marketing of various life-saving and essential drugs. KAPL is a WHO-GMP certified organization and with ISO accreditation.

- KAPL has been recognized for its total commitment to quality and services to cater to domestic and international markets. There are 02 manufacturing Plants operating in India.
- KAPL want to establish their *Bulk drugs and intermediates plant* in Vikram Udyogpuri, DMIC, Ujjain (MP), for this KAPL acquired land of 50 Acres from MPIDC, Ujjain. The total quantity of manufacturing product will be 1000 MT/Year.
- The project falls under 5 (f) category of the EIA Notification & its amendments issued by the Ministry of Environment & Forest vide S.O.1533 (E), dated September 2006, & its amendments.
- The project is in notified industrial area so no public hearing is required as industry falls in a government notified industrial area (DMIC-Vikram Udyogpuri, Ujjain (M.P.))
- The total land area of the project site is 202343 m² at Plot No. 103& 104 and 110 to 116 at DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain (MP).
- Total cost of the project will be 275 Cr.
- We will develop **41.24%** green Area.
- The total land area of the project site is 202343 m². Plot is allotted in DMIC-Vikram Udyogpuri, Ujjain (MP).
- Fresh Water Requirement will be 2000 KLD & Supplied By DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain

DETAILS OF PRODUCT

S.No.	Products	Total quantity /Annum
1	7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA)	1000 MT/Year

- ✓ 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA) is an important intermediate compound in the production of cephalosporin antibiotics. It is derived from cephalosporin-C, which is a natural product obtained from the fermentation of certain species of fungi, such as *Cephalosporium acremonium*.
- ✓ It is widely used in the treatment of various bacterial infections.

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with along with following additional TORs as annexed in annexure-D:

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. Inventory of existing trees & detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
3. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
4. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
5. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
6. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
7. VOC should be monitored in the AAQ.
8. All MSDS should be provided with the EIA report.
9. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
10. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
11. Details of any waste at present lying within the plant premises and if yes, same should be discussed in the EIA report with its disposal plan.
12. Inventory of existing and proposed machinery and if any existing machinery proposed to be used same shall be presented in the EIA report.
13. PP should explore possibility of using Biofuel based technology in boilers.
14. Compatibility of raw material storage.

14. Case No 9965/2023 Shri Girish Tiwari, HPA, M/s Deft Chemicals Private Limited, Plot No. U16, U17, U21 and U22, Industrial Area, Malanpur, District-Bhind (MP)-477116 Prior Environment Clearance for Bulk Drugs, API production and its intermediates at Plot No. U16, U17, U21 and U22, -Village-Malanpur, Tehsil-Gohad, District-Bhind (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Bulk Drugs, API production and its intermediates at Plot No. U16, U17, U21 and U22, -Village-Malanpur, Tehsil-Gohad, District-Bhind (MP).

During presentation, PP has informed that the old premises of abandoned unit Atlas Cycle was taken over by the M/s Deft organics with all existing infrastructure and shown photographs also. The relevant documents were also submitted with the application. Hence the case does not come under violation category.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with along with following additional TORs as annexed in annexure-D:

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. Inventory of existing trees & detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
3. Details of C&D waste generation and management.
4. Submit land transfer document with the EIA report.
5. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
6. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
7. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
8. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
9. VOC should be monitored in the AAQ.
10. All MSDS should be provided with the EIA report.
11. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
12. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
13. Details of any waste at present lying within the plant premises and if yes, same should be discussed in the EIA report with its disposal plan.
14. Inventory of existing and proposed machinery and if any existing machinery proposed to be used same shall be presented in the EIA report.
15. PP should explore possibility of using Biofuel based technology in boilers.
16. Compatibility of raw material storage.

15. Case No 9948/2023 Shri Mukesh Mishra, Owner, R/o Shakti Nagar, Sanwaliya Rundi, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (13034 Cum per annum) (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

आज दिनांक 15/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश मिश्रा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विजय मिश्रा, जियोग्रीन इन्वायरो हाऊस प्रा.लि.लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 101 दिनांक 13/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 470 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 107 मीटर पर नदी एवं पश्चिम दिशा में 64 मीटर पर प्राकृतिक नाला स्थित है, इनके संरक्षण हेतु कार्य योजना परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 101 दिनांक 13/01/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है। आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 470 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 107 मीटर पर नदी एवं पश्चिम दिशा में 64 मीटर पर प्राकृतिक नाला स्थित है, इनके संरक्षण हेतु कार्य योजना परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान के ढलान को देखते हुए सेटलिंग टैंक ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तावित करे।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

16. Case No 9899/2023 Shri Manmohan Kochhar, Proprietor, M/s Elite Engineers, 48, Narmada Road, Opposite Johnson Towers, District-Jabalpur (MP) Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" at Plot No.-62, 63, 64, 65 Umariya Dungariya Industrial Area, Shahpura, Umariya, District-Jabalpur, (M.P.)

This is case of Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" at Plot No.-62, 63, 64, 65 Umariya Dungariya Industrial Area, Shahpura, Umariya, District-Jabalpur, (M.P.)

In the SEAC 645th meeting dated 15.05.2023 the case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) and Shri Divya Chourasia , Authorized Signatory on behalf of PP. wherein PP submitted Following salient features of the project:

- M/s Elite Engineer is operating one unit in the Jabalpur city which is a proprietary concern established around 21 years back with 100 kg per hr. of Incinerator. The unit is running well and growing in each of the year. Now almost 350 hospitals are the customer of the firm. Recently few more work explored by the promoter and succeed in getting the Government hospital works at Narsinghpur, Mandla, Seoni, Balaghat, Dindori etc. Few new private hospitals of these areas are also added in the customers list. The plant become old and to comply the new norms of CPCB, an Incinerator of 200 +100 kg/hrs.(fixed hearth based) with chimney and effluent treatment plant is proposed. A Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF) is a set up where bio-medical waste, generated from a number of healthcare units, is suitably treated to reduce adverse effects that this waste may pose. The treated waste may finally be sent for disposal in a secured landfill or for recycling purposes.
- Proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200 kg per hour static kiln based bio medical incineration project, includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility. Following will be the capacity of the facility:

Sl. No.	Equipment	Number	Installed Capacity
---------	-----------	--------	--------------------

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

1	Static Kiln	2 Nos.	200 +100 kg/hr.
2	Autoclave	1+1Nos.	200 Lit/Charge
3	Shredder	1+1Nos.	50kg/hr.
4	Effluent Treatment Plant	1Nos.	10 KLD
5	Plastic Extruder System	1 No	250kg/hr.

Location	Total no. of HCF, s being covered	Total number of Beds	Estimated waste quantity in kg
Around 75KM	343 (Jabalpur, Katni, Seoni, Mandla, Narsingpur, Balaghat, &Dindori)	7605	1950 kg per Day

The committee after discussion asked PP to submit following clarification that this is a modernization of existing unit in-situ or ex-situ ? or replacement/ shifting of existing unit with enhancement of capacity at same district place? Please clarify in the light of gap analysis under CPCB/MPPCB guidelines.

The project proponent submitted clarification on 25.05.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 645th meeting held on 15.05.2023

The query reply was discussed SEAC in the 653th meeting held on 15.06.2023 wherein PP's Environmenta Consultant submitted that our existing our existing unit quite old and established around 21 years back with 100 kg per hr. of Incinerator in the city of Jabalpur. Now Habitation is coming close to the existing unit which will may generate issue in future, hence we have decided to establish new unit of 200 + 100 Kg of static incinerator at designated industrial area at Umriya Dungaiya Industrial Area, Shahpura, Jabalpur (MP). The autoclave and shredder of old unit will be used in new unit and whenever new unit will be operative, the old unit will be shut down. As far as gap analysis is concerned, following are data which is also available in annual report of MPPCB

Location	Total no. of HCF, s being covered	Total number of Beds	Estimated waste quantity in kg
Around 75KM	446	8382	2025

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

With the establishment of new unit of 200+100 kg, we will be able to incinerate about 1600 kg to 2000 kg per day in the new unit.

After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- a. Capacity assessment of proposed facility with the existing Bio-medical waste Generation in the EIA report.
- b. As per MPPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities one district has one facility hence PP shall plan only for Jabalpur district.
- c. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
- d. Facility should be developed in accordance with the provisions made in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by GOI and Guidelines published by CPCB & MPPCB for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities.
- e. Thus PP shall justify their site selection & location criteria as per clause 6(b) of CPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment & Disposal Facility with all sensitive's features.
- f. Capacity
- g. If any ground water abstraction is proposed, the permission from CGWB shall be submitted with EIA report .
- h. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWT facility within 75 Kms.
- i. Land use – diversion (if any) documents shall be submitted with EIA report.
- j. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- k. Detailed Water balance shall be submitted with EIA report.
- l. Elaborate in the EIA report considering that the proposed technology is “Best Available Technology” of CBWTF.
- m. Plume Dispersion modelling study wrt nearby habitations shall be carried out and result discussed in the EIA report shall be conducted.
- n. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- o. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- p. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 जून 2023

- q. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- r. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
- s. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
- t. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance in the EIA report.
- u. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.
- v. If any case is under consideration in any court of law with respect to this facility, same shall be reported/decision taken by court of law (orders/judgments) with its chronology till date in EIA report.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 जून 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minal Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes compliance commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

653वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 15 जून 2023

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर